

[श्री सुल्तान सिंह]

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि महीने में एक दिन मेहरबानी करके मिनिस्टर जाकर गांव में देखें, वहां सर्वे करें। जो दिल्ली के नजदीक गांव हैं, वहां आप चल दें, वहां सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके जो एक्सपर्ट हैं, उनको साथ ले लीजिए और अपने साथ बैठाइए। एक गांव से आपको सारे हिन्दुस्तान का नक्शा नजर आ जाएगा।

तो मेहरबानी करके इन बातों की तरफ ध्यान दें ताकि यह देश बचे और किसान की तरक्की हो। आपने जो क्राप इंसोरेंस की स्कीम लागू की है, उससे किसानों में बहुत उत्साह है और उसके लिए वह बहुत खुश हैं। लेकिन स्कॉम इंप्लेमेंटेशन पर भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि स्कीम तो आ जाती है अच्छी, लेकिन बाद में उसमें जाकर ब्लेक-मेलिंग शुरू हो जाती है। उससे भी हमको बच के रहना है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

STATEMENT BY MINISTER

Increase in the Swantantrata Sainik Sanunan Pension

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Now, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs will make a statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, I am glad to announce in the House that the Government have decided to increase the quantum of monthly pension admissible to freedom fighters and the widows of the deceased freedom fighters under the Swatan-

trata Sainik Samman Pension Scheme to Rs. 5001- per month. The increased rates of pension will be effective from 1st June, 1985.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT—contd.

श्री बीरेन्द्र वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। देश के किसान ने कड़ा परिश्रम कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्म-निर्भर बना दिया है। गत दो वर्षों में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दो वर्षों में 6.6 प्रतिशत खाद्यान्नों के भाव में गिरावट आई है। पिछले वर्ष गेहूं और चावल के उत्पादन में देश में कीर्तिमान स्थापित हुआ। लेकिन गेहूं के मूल्य में 3.8 प्रतिशत और चावल के मूल्य में 5.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे मान्यवर, जाहिर है कि किसान जब अधिक पैदा करता है, और अधिक पैदा करने के लिए बीज पर, खाद पर, पानी पर, कीटनाशक दवाइयों पर और मजदूरी अधिक व्यय करता है और अधिक उत्पादन करता है, उसके दुर्भाग्य से कृषि-उत्पाद का मूल्य गिरता है और अलाभकर होता है। इसके बिल्कुल विपरीत उद्योगों में जब उत्पादन बढ़ता है, तो उद्योगपतियों का पौ-बारह होता है।

मान्यवर, मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि किसान ऐसा अभाग है कि जब वह अपने खेत पर जाता है, उसका उत्पादन बहुत उत्तम और बढ़िया होता है, तो अपनी फसल को देखकर खुश होता है। लेकिन फसल जब मण्डी में लेकर जाता है, तो भाव को देखकर रोता है और जब उसकी पैदावार गिरती है, तो अपने खेत की फसल को देखकर रोता है।

अच्छी फसल होती है, भाव गिरता है तब रोता है, खराब उत्पादन हो तो खेत की मेंड़ पर खड़ा होकर रोता है। उस अभाग के लिए दोनों हालत में रोना है

इसके विपरीत उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है तो उनका लाभान्वित बढ़ता है। अभी हाल में क्या हुआ? आलू का उत्पादन बहुत हुआ, किसान ने 200 रुपये क्विंटल आलू का बीज खरीदा, भारी खर्च किया उस के उत्पादन पर, उत्पादन भी बहुत हुआ, लेकिन बीस-पच्चीस रुपये क्विंटल आलू बिका। बहुत से जिले ऐसे हैं। जहाँ किसान ने आलू को खोद कर निकालना उचित नहीं समझा। जितना इनवेस्टमेंट किया था, वह तो गया ही, आलू भी बर्बाद हो गया, उस की मेहनत भी गयी। पिछली दफा धान का मूल्य भारत सरकार ने 142 रुपये मुक़र्रर किया, लेकिन कोई क्य एजेंसी एक महीने तक नहीं भेजी गयी। नतीजा यह हुआ कि सहरनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर तथा दूसरे जिलों में जो भाव निर्धारित था उस से 15-20 रुपये क्विंटल कम पर किसान को मजबूर होकर अपना चावल बेचना पड़ा। इसी प्रकार की स्थिति गेहूँ की चल रही है, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहरनपुर हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, सभी जिलों में जो मुक़र्रर कीमत है उस से कम भाव पर मजबूर होकर किसान को बेचना पड़ता है। जहाँ तक मैंने आलू की बात कही, किसान से डिस्ट्रेस सेल पर शीतगृह वाले आलू खरीद लेते हैं 25 रुपये क्विंटल पर और अपने शीतगृहों में रखते हैं और सारा मुनाफा ले जाते हैं। दूसरे शीतगृहों में गूड़ रखने लगे हैं। सरकार ने बैंकों से कर्ज दिलवाया, सरकार ने बिजली की व्यवस्था की, लेकिन किसान वहाँ अपना आलू नहीं रख सकता, मुनाफे की दृष्टि से वे लोग गूड़ रखने लगे हैं। क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में आलू हों रखा जायेगा। मान्यवर, इस बात की व्यवस्था करिये कि जो छोटे किसान हैं, आलू उत्पादक हैं, गरीब आदमी हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी आलू रखने के लिए, न कि व्यापारियों को जो डिस्ट्रेस सेल पर आलू खरीद कर अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में भर देते हैं।

तीसरी बात मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूँ कपास के बारे में। कपास का भाव गिरा, लेकिन कपास से

जो सूत और कपड़ा बना उसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं और सरकार बैठी हुई देखती है। सरकार न उस को ठीक मूल्य दिला सकी और न बढ़ते हुए कपड़े के मूल्य को रोक सकी।

जहाँ तक गेहूँ की कीमत का सवाल है, सरकार ने अभी इस अधिवेशन में गेहूँ की 5 रुपये क्विंटल कीमत बढ़ाई है। 3.5 प्रतिशत गेहूँ की कीमत बढ़ी है। आंकड़े को उठा कर देखें मंत्री जी, उत्पादन लागत 10 प्रतिशत बढ़ी है और मूल्य में बढ़ोतरी 3.5 प्रतिशत की जाती है। यह न्याय है या अन्याय है?

आपने कमीशन आफ कास्ट एन्ड प्राइसेज नाम कर दिया। पहले भी कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखा जाता था। आपने कमीशन का नाम बदला प्रचार करने के लिये, ठीक हो सकता है कि हमने कदम उठाया कि कास्ट को आधार मानकर प्राइस मुक़र्रर करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि कास्ट 10 प्रतिशत बढ़ गई उत्पादन में और आपने साढ़े 3 प्रतिशत वृद्धि की है। कहीं तक किसान के साथ न्याय है? आप विदेशों से किस भाव पर मंगाने हैं। विदेशों से जो गेहूँ आता है वह देश में 222 रुपये क्विंटल पड़ता है। सबसिडी देकर आप उपभोक्ताओं को खिलाने हैं।

अपने देश के किसान को दें तो बाहर से आप को मंगाने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन दोषपूर्ण है हमारी नीतियाँ। 1981-82 में 84 लाख 38 हजार टन चीनी का उत्पादन इस देश में किया। सारे संसार में प्रथम स्थान इस देश का हुआ लेकिन क्या हुआ अगले वर्ष। 1982 में 82 लाख 32 हजार टन उत्पादन हुआ और दो साल के बाद क्या हुआ। बफर स्टॉक बनाया गया था लेकिन बफर स्टॉक को भी बिखेर दिया और बहा दिया। किस हिसाब से आपने चीनी को रिलीज किया किस के हित में किया? क्या वह स्मॉलिंग के हित में किया जा रहा था? पाकिस्तान और बंगला देश के लिये किया जा रहा था? किस के हित में किया जा रहा था? बफर स्टॉक को हमने

[श्री वीरन्द्र वर्मा]

किस तरह से लुटाया है कि सरकार ने भजबूर हो कर पिछले साल 5 लाख टन चीनी का आयात किया गया और इस साल 10 लाख टन चीनी का आयात करना पड़ेगा। यह हमारी दोषपूर्ण नीति का नतीजा है। दो साल हम अपना उत्पादन बढ़ाते हैं, फिर भी दो साल तक घटाते हैं। तो क्या हम इयर टू इयर नीति बनाते रहेंगे या पांच या दस साल के लिये कोई नीति बनाते हैं। हमारी व्यवस्था तो पांच या दस साल के लिये होनी चाहिये और मैं ईमानदारी से महसूस करता हूँ कि जिस समय श्री एस० के० पाटिल साहब देश के कृषि मंत्री थे उन्होंने कहा था आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में, और मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ और उनसे मैं शत प्रतिशत सहमत हूँ। उन्होंने कहा था कि प्रारम्भ से ही इस देश में जो कृषि की नीति है वह उपभोक्ता पोषक है। कंज्यूमर ओरियेन्टेड है। वह किसान पोषक नहीं है इस लिये मैं आप की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ कि 1970-71 के आंकड़ों के अनुसार कृषि जन्म पदार्थ जितने हैं, उन के मूल्यों में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों में 70 प्रतिशत की वृद्धि 14, 15 वर्षों में हुई जब कि इतने समय में ही औद्योगिक उत्पादों में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्या खेती में लगे आदमी की आमदनी में और उद्योग में लगे आदमी की आमदनी में अंतर नहीं बढ़ता जायेगा। तो क्या हम समाजवाद इसी आधार पर स्थापित कर सकते हैं। किस तेजी के साथ गैर किसान लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होती जा रही है और किसान की आमदनी में गिरावट आती जा रही है इस को देखा जाये। मैंने बताया कि गिरावट आयी 6.6 प्रतिशत की। खाद्यान्न के मूल्य में पिछले दो वर्षों में गेहूँ के मूल्य में गिरावट आयी है, चावल के मूल्य में गिरावट आयी है और इसी कारण 1980 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि कृषि जन्म पदार्थ और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता, पैरिटी आफ

प्राइस मेंटेन की जानी चाहिये। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे अपने उत्तर में कि सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गयी समाजवाद की दृष्टि से गरीब इंसानों को ऊपर उठाने की दृष्टि से। उन्होंने क्या कोशिश की है पैरिटी आफ प्राइस को मैन्टेन करने के लिये और आप अंदाजा लगायेंगे कि जब किसान अच्छी पैदावार करेगा तो उस के उत्पादन का मूल्य गिरेगा और जो चीजें वह खरीदेगा उन की उसे अधिक कीमत देनी पड़ेगी। तो किस तरह से वह खुशहाल हो सकता है। किस प्रकार उस की आर्थिक अवस्था में सुधार हो सकता है। मैं कृषि उत्पाद के लिये सब से महत्वपूर्ण बीज को मानता हूँ। लेकिन आप मुझे से सहमत होंगे कि बीज को चाहे वह नेशनल सीड कारपोरेशन हो या कोई भी एग्री-कल्चरल यूनिवर्सिटी हो उस में बीज की कीमत क्या मुकर्रर होती है 400 रुपये, 350 रुपये क्विंटल। यह कीमत नेशनल सीड कारपोरेशन ने मुकर्रर की है। क्या यह असहनीय नहीं है। हमारे यहाँ अलाभकर जोत वाले किसान हैं, सीमांत किसान हैं। क्या वे 350 या 400 रुपये क्विंटल का दाम दे सकते हैं? क्या वे इस बीज को खरीद सकते हैं, नतीजा होगा कि जो खुशहाल किसान है वह उस को खरीदेगा और वह उसका फायदा उठायेगा मेरी गुजारिश है कि गरीब आदमियों को सब्सिडाइज कर के नो-प्रोफिट नो लॉस के आधार पर बीज का वितरण कराने की आप कोशिश करें।

मान्यवर, दूसरी मेरी गुजारिश आपसे यह है कि सन् 1962 में इस देश के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने यह देखा कि किसान फसल के टाइम पर अपने अनाज को फँकता है, डिस्ट्रेस सेल करता है। इसलिये उसको सहूलियत देने के लिये वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई थी। नतीजा क्या निकला। सन् 1962 से आज 23 वर्ष हो गये हैं, 1962 से आज तक वे आंकड़े उठाकर देख लीजिये, जिस अभाग किसान के लिये यह भंडार निगम बनाया गया था, उसका एक फीसदी अनाज भी इन भंडार के गोदामों में नहीं है।

क्या व्यापारियों के लिये यह बनाये गये थे। सारा अनाज व्यापारी वहाँ ले जाते हैं, पहले किसान को लूटते हैं और फिर उपभोक्ता को लूटा जाता है। इसलिये किसान के अनाज को भंडार निगम के गोदामों में रखने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता है जिस से कि किसान डिस्ट्रिक्ट सेल से बचाने के लिये अपना अनाज उसमें रख सके और उससे फायदा उठा सके।

श्रीमन, फूड कारपोरेशन की स्थापना 1965 में हुई थी, बड़ी आशाओं के साथ इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, फिलफरेज के ऊपर, डेमरेज पर हर साल इसका नुकसान बढ़ता जाता है। मेरा पास आंकड़े हैं, सन 1981-82 में इसे 116 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और 1982-83 में 27 करोड़ और बढ़ गया, यानी 143 करोड़ 60 लाख का नुकसान हुआ। 1983-84 के आंकड़े उठाइये, 1984-85 के आंकड़े उठाइये, यह भूरा हाथी जिस पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक नुकसान आपके यहां होता हो, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है कि किस प्रकार से उसमें सुधार कर सकते हैं।

मान्यवर, दो तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, प्रति वर्ष बाढ़ के कारण इस देश के किसान की फसल, उस गरीब आदमी के मकान, उनके पशु आदि की बरबादी के कारण अरबों रुपये का नुकसान होता है। सरकार प्रति वर्ष कुछ योजनाएं बनाती है, उनकी सहायता करती है, मकान गिर गए, उनकी फसल नष्ट हो गई, उनके पशु मर गए तो उनको सहायता देती है। मेरी गुजारिश है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। बाढ़ की तबाही और बरबादी से बचाने के लिए लम्बी चौड़ी योजनाएं बनाइए ताकि किसान और देश को इससे बचाया जा सके। (समय की घंटी)

मान्यवर, कीटनाशक दवाओं का बहुत प्रयोग किसान करता है। वित्त मंत्री जी

ने और बहुत सी चीजों में आयात शुल्क में छूट दी है लेकिन कीटनाशक दवाओं में क्यों नहीं दी जो किसान — के लिए विदेशों से मंगाते हैं। 12 उद्योगों को वित्त मंत्री जी ने लाइसेंस मुक्त किया लेकिन एक भी कृषि उद्योग को यह राहत नहीं दी। इस पर भी आप विचार करें चाहे वह वनस्पति का उद्योग हो चाहे गन्ने की मिलें हों या दूसरी प्रकार की मिलें हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, बड़ी चर्चा की गई कि सौ जिलों में इंश्योरेंस कर रहे हैं। लेकिन कृपा करके किसानों का कांफ्रिहेंसिव इंश्योरेंस कीजिए चाहे उसका ट्यूबवैल हो, दूध के पशु हों या खेती के पशु हों, उसका फार्म-हाउस हो, उसके जितने भी उत्पाद हैं, जिस तरह से आम इंडस्ट्रीज का करते हैं चाहे रुई का गोदाम है, चाहे और भी जलने वाले, आग लगने वाली दूसरी चीजें हैं, उन सब का आप इंश्योरेंस करते हैं, तो आपको किसान का भी उसकी सभी चीजों के लिए कांफ्रिहेंसिव इंश्योरेंस करना चाहिए। (समय की घंटी)

एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मान्यवर, हमारे देश में स्टेट फार्म कारपोरेशन की तरफ से संचालित 15 फार्म हैं जिनका रकबा 38229 हेक्टेयर है।

5 P.M.

जिसका अर्थ हुआ साढ़े 95 हजार एकड़। पिछले दो वर्षों में देश में कीर्तिमान स्थापित हुआ खाद्यान्न के उत्पादन में। लेकिन आपका नुकसान 38 हजार 200 हेक्टेयर के इन फार्मों पर हुआ। आपका उत्पादन इन दो वर्षों में गिरा। मालूम है आपको कितना नुकसान हुआ। आपको नुकसान हुआ 2 करोड़ 79 लाख का इन फार्मों पर आपको हमारी चुनौती है। इतने बड़े नुकसान की, जो हमारे पहले चेयरमैन थे स्टेट फार्म कारपोरेशन के उन्होंने शिकायत की मैनेजिंग डायरेक्टर की, जो एसोसिएशन हैं उसने शिकायत की। उसने शिकायत की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को।

लिख कर शिकायत की। मिनिस्टर को लिख कर शिकायत की। लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : चुनौती नहीं शर्म की बात है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : तिलहन और दलहन 1978 और 79 में कितना पैदा हुआ इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। योजना पर योजना आपकी बनती जा रही है, खर्च पर खर्च बढ़ता जा रहा है। 78 और 79 में दलहन और तिलहन का उत्पादन जितना आपके देश में हुआ था पिछले वर्ष उससे कम हुआ। किस प्रकार की योजनाएं हैं आपकी? किस तरह से आप अपनी योजनाओं को सफल बनायेंगे? एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा कि आज गन्ना उत्पादकों का 133 करोड़ रुपया मिल-मालिकों के ऊपर बकाया है। कानून यह कहता है कि 15 फीसदी का सूद मिलेगा अगर 14 दिन की देरी से पैमेंट करता है। हिन्दुस्तान की एक भी शुगर फैक्टरी के एक भी मिल-मालिक ने एक भी किसान को एक नया पैसा भी सूद का नहीं दिया। कृषि मंत्री जी आपने बफर स्टॉक बनाया मिल-मालिकों के साथ। शुगर आपने रखी और उस शुगर को आपने मिल-मालिकों को रखने के लिये सूद दिया। लेकिन उस बद-किस्मत किसान को कानून के होते हुए भी एक नया पैसा सूद का नहीं दिला सके क्या अपनी सफलता को इससे आँकेंगे? मैं अधिक बात न कहता हुआ आपसे यह गुजारिश करूंगा कि नीति आप कृषक और कृषि के हित में बनाइयेगा जिससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। अंत में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितनी फल सब्जी पैदा होती है सरकारी आँकड़ों के अनुसार 11 अरब रुपये की सब्जी और फल प्रतिवर्ष नष्ट होती है। क्या यह हमारे लिये चुनौती नहीं है। जिस देश में गरीब आदमी को न फल मिले, न सब्जी मिले खाने को उस देश के अंदर 11 अरब रुपये के 36 करोड़

टन फल व सब्जी नष्ट हो जाए और उसके लिये डिम्बाबन्द की व्यवस्था न की जाए, न निर्यात की व्यवस्था की जाए तो इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

SHRI PARVATHANENI UP-
ENDRA: Mr. Vice-Chairman, Sir, the most hapless person, who is in the most unenviable position today, is the Indian farmer. We pay only lip-sympathy to this halfed, ill-clad, uneducated species who is groaning under the weight of poverty and shackles of the money-lenders. If you look at the Indian agricultural scene, we come across three paradoxes. On the one side, there is a record production of over 150 million tonnes. But, at the same time, the per capita availability of foodgrains remains static as it was in 1956, and much less than what it was in 1977-78. Secondly, the farmer, who sweats day in and day out gets a very low price for his produce, but the consumer, on the other side, pays through his nose. It is only the middlemen who are reaping the benefit of the higher agricultural production.

Thirdly, while for some agricultural produce, the price is so unremunerative, particularly the sugarcane and oilseeds, the farmers are stopping to cultivate these crops forcing the Government to import sugar and edible-oils. Unless we remove these three paradoxes, we will never be able to improve Indian agriculture.

I would like particularly to mention the role of the Commission of Agricultural Costs and Prices. A few days ago, the Minister of Agriculture said: "While fixing support procurement prices, it is ensured that these prices cover cost of production and also provide a reasonable margin of profit." Leave alone

too reasonable margin of profit, I wonder whether the prices fixed by this Commission are adequate to cover the cost of production for agricultural produce. For example, the Commission has fixed Rs. 135 for paddy; Rs. 140 for sugarcane and Rs. 1200 for tobacco and roughly about Rs. 550 for cotton. Here, you find that for sugarcane, the Commission itself has suggested a higher price of Rs. 160 but the Government, for reasons not known, has scaled it down to Rs. 140, which is very unremunerative to the farmers. As a result, in a number of places, the farmers have stopped cultivating sugarcane. In my own State, Andhra Pradesh, the position is so bad that a large number of sugar mills are not getting sugarcane because the farmers have stopped cultivating this crop, and the State Government has announced a support price of Rs. 55 and also incentive price of Rs. 10 over and above the price fixed by the Central Government. Still the position is worse.

Similarly, for tobacco, whereas the farmer gets nearly Rs. 1200, the agent who procures the tobacco for export or for internal consumption, gets roughly Rs. 650 more than what the farmer gets. Similarly, in the case of cotton, the Government of India has given an export order for the marketing federation but when you go to the market, the entire crop has been cornered by agents and nothing is left for cooperative institution to procure and the Government agencies are forced to buy from these agents at a very high price, cotton for export for which they have got the order. This is a big vicious circle. In spite of the anxiety of the Commission for Agricultural Costs and Prices, the farmer is not getting his due price.

Another point which you find is, whereas production has been increasing, productivity is going down. Even today if you compare per acre yield of paddy in our country with some of the South-Asian countries, it is so low and as a result, production also is suffering to a very large extent. When you come to the cost of inputs, the cost is so high. Sometimes, the costs of inputs like fertilisers and pesticides are abnormal which are beyond the reach of the small and marginal farmers. The production in the public sector fertiliser units is going down year after year. As per Government's own admission, all the fertiliser units, nearly 22 of them in the public sector, have not reached capacity production' in 1984-85. Similarly, Hindustan Insecticides also has recorded production below its target. As a result, these inputs had to be imported at a very high cost and the farmer suffers in the process. The Government of India has undertaken a very good scheme called 'Intensive Fertiliser Promotion Campaign', as a pilot project in about 104 districts in the country. But I feel, this scheme should not only be implemented with greater vigour, but this should also be extended to more districts.

Another aspect which has been neglected is the need for improving the irrigation potential, particularly, in a State like Andhra Pradesh. Sir, as you are very well aware, Andhra Pradesh is surplus in foodgrains. The production is not only enough to feed the people in the State, but a large quantity is exported to other States also. But there is a large irrigation potential in the State which, when developed, will lead to greater food production, as a result of which people in the other States will also be benefited. In this con-

[Shri Parvathaneni Upendra] nection, I would like to refer to the Polavaram Project, costing nearly Rs. 1200 crores. This should be taken up as a national project and also the Telugu Ganga Project, which would irrigate roughly four and a half lakh acres, in the Royal-seema area. If both these projects are taken up, Andhra Pradesh would be able to supply a few more lakh tonnes of foodgrains to the country.

Sir, the Government statistics also show that the production of pulses has gone down last year. As I have already mentioned, the oilseeds production has also gone down; it is going down as a result of the unremunerative prices. Sir, I would also like to refer in this connection to the announcement made by the Finance Minister in Ms Budget Speech, in regard to the crop insurance scheme, which the Government wants to introduce from 1985 Kharif season. I do not know whether the modalities of this scheme have been worked out. But it should not meet the same fate as the other schemes announced earlier. This is a long-pending measure and the Government should go ahead with the implementation of this scheme.

Sir, there is another aspect which needs emphasis. This is in regard to strengthening the credit system for the farmers. But at the moment, they are facing a lot of hurdles in getting the required credit because a number of banks are involved. The Andhra Pradesh Government has thought of a scheme for supplying credit from a single window. It is called the 'Single Window Scheme' and it is awaiting clearance from the Central Government. The Agriculture Ministry is already seized of the matter. I would request

that this scheme should be cleared as early as possible. And not only Andhra Pradesh, but other States should also be encouraged to undertake such a scheme.

Sir, in the case of die rural development schemes, particularly, the NREP and the IRDP, the Government has announced its intention to undertake an evaluation study particularly in regard to rural employment which! is sought to be created through the NREP scheme. I do not know whether that evaluation study has been undertaken, but it is high time that evaluation of both the NREP and IRDP schemes is taken up now and also under these schemes permanent assets are created. One of the latest scheme is construction of school buildings. I suggest that more attention should be paid to this project as well as to the construction of roads, hospital buildings, etc.

Another long neglected point is the protected water supply in rural areas. That should be given greater attention and schemes in this regard should be expedited.

In the scheme for creation of rural employment, youth should be given preference and I can mention, in this connection, the scheme introduced by the Andhra Pradesh Government in the implementation of the Telugu Ganga project where instead of the usual contractors youth organisations are given the civil engineering contracts of the nroject. This would not only involve the youth in the national building activities, but would also reduce" the cost of construction while providing employment to the rural youth.

The last point which I would like to touch upon is, the Govern-

ment has earlier started the Krishi Vigyan Kendras and only 89 have been, created in the entire country. If you want to educate the farmers, particularly the young farmers, in agricultural operations and modern technics, more and more such ken-dras should be started in the country where vocational training in agriculture can be given to thfe young farmers). With these few words, I would request the hon. Minister to give greater emphasis in ensuring a remunerative price to the farmers which is die crux of the whole problem.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। यह बात सही है कि किसानों की आर्थिक हालत जिस तरह से वह पैदा कर रहा है उसके मुताबिक सही नहीं है। किसान के अन्न को खा कर सारे नंसार की आंख खुलती है चाहे व्यापारी हो चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे कोई हो लेकिन मेरा कहना है कि किसान की तरफ उसकी समस्याओं की तरफ से आंख बंद नहीं होनी चाहिये, आंख खोल कर उनको समस्याओं को देखना और समझना चाहिये। अभी किसानों के बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि एक धारणा हो गई है कि वह अन्न का उत्पादन करता है तो साथ ही साथ वह उप-भोक्ता भी है, खरीददार भी है लेकिन इसकी तरफ ध्यान कम जाता है। उसके द्वारा पैदा की गई चीजों और खरीद की जाने वाली चीजों के भाव में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। यह बहुत बार कहा गया है लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं आया। मेरा यह एक छोटा सा सुझाव है इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिये। कारपोरेशन की चर्चा वर्मा जी ने की मैं तो उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन यह सच्चा है। मुझे भी थोड़े दिन उसका चैयरमैन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके चाटे के मधा कारण थे हम उस में गहराई से गये। सबसे बड़ा कारण था वहाँ मवेशी बहुत रखे जाते थे। उन्हें
288 RS-10

कर्मचारी जो पहले फार्मों पर थे और पहले चैयरमैन और एम० डी० वगैरह थे उनको निकलवा नहीं सके पुलिस की मदद से हमने वहाँ के कर्मचारियों की मदद से फार्मों से एक-एक मवेशी को निकाल दिया और इतने पशु निकले कि हम को सूरतगढ़ के पास गउशाला खुलवाना पड़ी। कोई खरीदार नहीं था न गाय का, न बैल का बड़ी तेजी से वे निकले। हमने वहाँ सिंचाई के लिये एक नहर की योजना बनाई सूरतगढ़ में और इसके लिए केन्द्रीय सरकार से भी ग्रांट ली गई। उसमें बहुत सी अड़चनें हुई लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। वहाँ के लोकल एम० पी० भी थोड़ा सा खिलाफ रहे। लेकिन फिर भी हमने ग्रांट लेकर उस नहर को मंजूर कराया। रुपया अभी गया हुआ है बननी तैयार है।

चिगलवरम एक फार्म है तमिलनाडु में उस पर छोटा डैम बनाने की स्कीम थी हमारा चीफ इंजीनियर कहता था नहीं बनेगा, तमिलनाडु, मद्रास का भी कहता था नहीं बनेगा। हमने जिद की, मुख्य मंत्री रामचन्द्रन से बात की। वहाँ एग्री-कल्चरल सेक्रेटरी कोई लेंडी थी, जब हमारी बातचीत हो रही थी तो वह ऐसे बोलती थी जैसे हम किसान के लिये कुछ करना नहीं चाहते थे, तमिलनाडु की जनता के खिलाफ हैं तब मैंने बहुत तेजी से कहा कि आपको एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी किसने बना दिया आप तो किसानों की दुश्मन लगती है तब जरा ठंडक लगी और रामचन्द्रन जी का ध्यान मेरी तरफ गया। मैंने कहा हम तमिलनाडु के किसान को अच्छा बीज देकर उसकी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं उसमें छोटे-छोटे डैम के लिये थोड़ा आपका लिखा हुआ चाहते हैं, मदद चाहते हैं बाद में खैर उन्होंने लिखा और उस जगह पर हम चीफ इंजीनियर को लेकर गये जहाँ के लिये वहाँ की गवर्नमेंट ने नामंजूर कर दिया था। हम जंगलों में पैदल घूमे और दो पहाड़ों के बीच में हमने एक जगह को तलाश किया। मैं बधाई दूंगा तमिलनाडु की गवर्नमेंट को और फिर वहाँ के चीफ इंजीनियर को इतने प्रभावित हुए कि उस डैम को बजाये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट के तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने खुद उतना मंजूर कर दिया मगर कंडीशन यह रखी कि आपके चिगलवरम फार्म को हम पानी

[श्री रामचन्द्र विकल]

के लिये प्राथमिकता देंगे। हमने भी मान लिया कि हमें पानी चाहिये।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अगर दिल से चाहे तो इन योजनाओं से मुनाफा हो सकता है। हमारे जमाने में यह मुनाफा था। आज एक एम० डी० की बजह से सारा घाटे में चला गया। चीफ इंजीनियर हमारा छुट्टा पर है घर पर तनख्वाह दो जा रही है, कोर्ट से स्टे लिया है। एग्जीक्यूटिव चीफ जो वहां का ईमानदार अफसर है जो हमारे एग्जीक्यूटिव की जानता है वह छुट्टा लेकर घर पर बैठा है। यह क्यों हो रहा है? लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हमने अपने सरकारी अफसरों को कह दिया था कि पड़ोसी किसानों को अपनी टेक्नीकल राय दो, किसानों को फार्म पर बुलाओ उनके घर पर जाओ उन्हें अच्छे बीज दो, अच्छा सलाह दो अगर हमारी मशीनरी खाली है तो किराये पर दो। जो किसान और फार्म के पड़ोस में जगड़े थे हमने वे मुकदमे वापस करा दिये, किसानों में आपस में भाई-भ्राता कराया, किसान फार्म में आने लगे और हमारे अफसर फार्म से वहां जाने लगे। अनेकों ऐसी योजनाओं में हमने यह कोशिश की तो सरकारी अधिकारी अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूं मैं नाम लेकर बता सकता हूं। सैयद हमिद हमारे एक कलक्टर थे जब पंजाब में बाढ़ आई तो किसानों से मिलने गये। मैं उनका नाम पब्लिक स्पीच में लेता हूं। हमारे कैप्टन भगवान सिंह कलक्टर थे जो किसान की छोल पर जाकर बैठते थे, किसानों से पूछते थे। चतुर्वेदी जी शाहजहापुर में एक कलक्टर थे जिन्होंने रामगंगा के एक दुआवे में चढ़े डालकर बसें चलवा दी वहां कालेज बनवा दिये, स्कूल बनवा दिये, शाहजहापुर में सड़कें बना दी अल्लाहगंज में एक अस्पताल का बड़ा भारी उद्घाटन किया। तो सरकारी अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं। सरकारी अधिकारी अगर चाहें तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सरकारी अधि-

कारी बहुत जगह स्वतंत्र हो रहे हैं। उन पर सरकार का प्रिय रहना चाहिये।

मुझे कृषि मंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक कृषि कालेज था कानपुर में, हमने 2 यूनिवर्सिटियां बनवाई फैजाबाद और कानपुर में। कृषि कालेजों के साथ हमने गांव लगा दिये और वहां के एक्स्पर्ट्स को कहा कि आप इन गांवों को टेक्नीकल ज्ञान दें। किसानों का कितना फायदा हुआ है यह वहां के गांवों में देखिये। मगर जरूरी यह है कि हम अधिकारियों पर कंट्रोल करें, किसानों के साथ उनकी सद्भावना हो। दुर्भाग्य यह है कि किसान बेपढ़ है उसको अंग्रेजी में ऐसे कागज, फार्म मिलते हैं कि बेचारा उनमें उलझा ही रहता है। तो भाषा भी किसान को होनी चाहिये तभी किसान आपकी बातों को समझेगा। तो वह बहुत सी दिक्कतों हैं मैं थोड़े समय में कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि सरकारी अधि-कारियों पर अगर कंट्रोल हो जाय तो हमारी जो सारी घाटे की योजनाएं हैं वे मुनाफे में हो सकती हैं। सारे कार-पोरेशन घाटे में क्यों हैं? केवल इसलिए है कि सरकारी अधिकारियों में अपनी भावना नहीं है, राष्ट्रीय भावना हमारे देश में दुर्भाग्य से नहीं बनी है। मैं तो अपने अधि-कारियों से यही कहता था कि यह काम तुम्हें अपना करना पड़ता तो तुम क्या करते उस वक्त? अगर यह भावना आ जाय तो हमारे कारपोरेशन जो घाटे में हैं जिनका कि वर्मा जी ने जिक्र किया सुन्ना यह है कि वे हमारे मुनाफे के फार्म हैं। उनकी साजिश से मैं जानता हूं घाटे में जा रहे हैं। केवल वहां के अधिकारियों के लड़ाई जगड़ें में। किसी का ध्यान ही नहीं है, वे सब भूल गए हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसान इस देश की आर्थिक रीढ़ है। सब लोग जानते हैं कि किसानों पर दैवी विपदाओं का सबसे बुरा प्रभाव होता है चाहे बाढ़ हो, ओला हो, वर्षा हो, अति वर्षा हो, सूखा हो, मवेशियों की बीमारियां हों इन सारी आपदाओं से किसान की कमर टट

जाता है और हर 5 वर्ष में काई न काई आपदा जरूर आ जाती है किसान पर, यह रूटीन सा है चाहे ओला पड़ जाय, पाला पड़ जाय, अति वर्षा हो जाय, हवा आ जाय इन दैवी आपदाओं में किसान की फसल . . . (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र वर्मा: सूखा है।

श्री राम चन्द्र विकल: सूखा है सरकंडे की बीमारी हो जाय, मवेशियों की बीमारी हो जाए, कभी-कभी तो हवा ऐसी चलती है कि जो गेहूं को मार जाती है, उसमें बीज रहता ही नहीं है। तो यह दैवी आपदाओं का मारा हुआ किसान है। फसल बीमा की योजना के लिए बधाई तो देते हैं, जैसे वर्मा जी कह रहे हैं, सौ गांवों में है। यह फसल बीमा के साथ-साथ मवेशी बीमा भी होना चाहिए और दैवी आपदाओं का भी बीमा होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य: किसानों को बोनस दिया गया है?

श्री राम चन्द्र विकल: बोनस पंजाब में दिया गया है। प्रधान मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। उन्होंने एलान किया है कि ऐसा बोनस पंजाब के किसानों को दे रहे हैं। मैं कई सालों से पंजाब में जा रहा हूं। यह पंजाब के किसानों की बड़ी मांग थी।

श्री बीरेन्द्र वर्मा: यह पंजाब सरकार दे रही है या केंद्र, यह बताइये?

श्री राम चन्द्र विकल: पंजाब सरकार भी तब देगी जब प्राइम मिनिस्टर ने एलान किया है। उससे पहले तो नहीं दे पा रही थी। उसका श्रेय तो प्रधान मंत्री को जायेगा ही जायेगा। . . . (व्यवधान) केंद्र, राज्य सरकारों को दो जगह में मत बांटो, किसान तो वैसे ही बंटा हुआ है। उसको कहीं से ही फायदा हो जाए, फायदा होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जिस तरह पंजाब के किसानों को बोनस के लिए कहा गया है इसी तरह सारे देश के किसानों को

बोनस देना चाहिए, क्योंकि सारे किसानों की हालत एक जैसी है। बिजली के मामले में सभी ने कहा कि बड़ी दिक्कत है। रेडियो में भी कभी-कभी सुनता हूं। 70 फीसदी जमीन सिंचाई से वंचित है। यह तो रोज हमारा सरकारी रेडियो कहता है कि 70 फीसदी जमीन सिंचाई से वंचित है। मंत्री जी तो खैर हम से ज्यादा जानते हों। 30 फीसदी पर पैदावार बढ़ा रहे हैं इस देश के किसान और जो बाहर से अन्न आता था, आज बाहर को अन्न और बीज देते हैं, खुद बीज भेजा है बाहर को और यह सौभाग्य है कि बाहर के देश हमारे एक्सपोर्ट भी मांग रहे हैं वहां पर फार्म चलाने के लिए। लेकिन अगर 70 फीसदी जमीन को पानी दे दिया जायगा तो क्या हाल होगा? सारी दुनिया को हिन्दुस्तान का किसान खाद्य-सामग्री दे सकता है। 30 फीसदी सिंचाई पर अगर इतना है कि आज हिन्दुस्तान बाहर को खाद्य सामग्री भेजता है तो वह 70 फीसदी पर जब सिंचाई की सुविधा हो जाएगी तब तो बहुत ज्यादा देश में पैदावार बढ़ जायगी। बिजली का दुरुपयोग होता है। लोग शादियों में कई-कई दिन पहले और बाद में रोशनी करते हैं। अगर देश को बनाना है तो इस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। शादी सुबह करके बारात शाम को विदा हो सकती है। इसमें क्या हर्ज है? थोड़ा सा सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा और बिजली की किफायत हो सकती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, पदें हटवा दो, बहुत सी बिजली बच जायगी। सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों में तीन-तीन घंटे बिजली और पंखे चलते हैं। मैंने खुद देखा है, वहां पर उस आदमी की भावना ही दूसरी हो जाती है। दुर्भाग्य से हमारे यहां कहावत है, सरकार से तेल मिले तो कपड़े मैं ले लो, निकल जायगा पर कपड़ा ही खराब हो जाएगा। पर सरकार से चीज मिलती है तो जरूर लो। इस भावना से इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, देश की बदकिस्मती हो रही है। इसलिए सारे देश भर में पदें हटवा दीजिए। जहां सूरज जा सकता है वहां उसकी

[श्री रामचन्द्र विकल]

रोशनी जा सकती है, रोशनी नहीं जाए तो पद लगा दें। (व्यवधान)
मैं आपको भी कह रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य : आपके पीछे पंखें चल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल : मैं यह नहीं कहता कि पंखें नहीं चलें। (व्यवधान)
यह भी अगर हो जाए कि अगर बैठें तो पंखें चला दें, नहीं तो बंद कर दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा मतलब तो बिजली की किरायत से है। बहुत ही मौकों पर जैसे शादियों में तो बहुत ही फिजूलखर्ची होती है। रात-रात भर बिजली दो दिन पहले से और दो दिन बाद तक बिजली चलती है। पंजाबी भाई तो दो घंटों में शादी करके लड़की को विदा कर देते हैं। दो घंटों में शादी सुबह बुलाओ, दस बजे तैयारी करते हैं और दो घंटों में शादी कर डालते हैं। हमें जहाँ से अच्छी बात मिले, लेनी चाहिए। सरकार से और समाज से भी मुझे यह कहना है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ठंडा करने की मशीन में भी बिजली जलती है

श्री रामचन्द्र विकल : मैं तो कहता हूँ कि यह भी हटवा दो। मैं तो गर्मी सर्दी सहने का आदी हूँ। तो मुझे यह कहना है कि पैदावार की खरीद-फरोख्त में सन्तुलन हो। कृषि का वैज्ञानिक और टेक्नीकल ज्ञान किसान तक जाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। आज किसान बैसा नहीं रहा जैसा कि पहले था। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि वह अच्छा बीज लेने के लिए झगड़ा करता है, अच्छी खाद के लिए झगड़ता है, बिजली के लिए, पानी के लिए वह झगड़ता है। इतना ही मेरा कहना है कि जितने भी विभाग हैं, चाहे बैंक हों, चाहे सिचाई विभाग या नहर विभाग के आफिसर हों, चाहे बिजली के आफिसर हों, वे जो किसान को परेशान करते हैं उस परेशानी को दूर किया जाए। इस

परेशानी के दूर होने से मैं कह सकता हूँ कि देश की पैदावार बहुत बढ़ सकती है। जिन दफ्तरों में किसान को परेशान किया जाता है, मुझे तो कैरों की यह एक कहावत याद आती है, जो कि सच्ची है, वह हमेशा यह कहते थे कि किसान तुम्हारे दफ्तरों में धक्के नहीं खाएगा, तुम किसान के दरवाजे पर जाओगे। मुझे बहुत से व्यावहारिक उदाहरण उनके मालूम हैं। आज हमारी सरकार का, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे हमारे बैंक के दफ्तर हों, वह किसान को दफ्तरों में ज्यादा धक्के न लगवाएं और जो किसान की जरूरत है, वह किसान को उसके पास पहुंचाएं। इससे किसान की पैदावार बढ़ सकती है और वह देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है।

मुझे इतना ही उपाध्यक्ष महोदय, कहना है कि यह किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, इस पर देश का आर्थिक ढांचा निर्भर करता है। इस किसान की सुविधा, चाहे वह कानूनी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सिचाई संबंधी हो, चाहे अच्छे बीज की हो, चाहे अच्छे खाद की हो, सारी सुविधाएं उसे ज्यादा से ज्यादा दी जाएं। इससे देश की समृद्धि होगी और सभी को खुशी होगी। देश की पैदावार भी बढ़ेगी और सबको उसका लाभ मिलेगा।

श्री वर्मा जी ने यह बात ठीक कही कि किसान की बदकिस्मती है कि किसान की जब कभी पैदावार बढ़ जाती है, तो उसके दाम घट जाते हैं तो किसान की फसल की कोई गारंटी होनी चाहिए और पैदा होने से पहले उसके दाम फिक्स होने चाहिए। चाहे गेहूं की पैदावार हो, चाहे गन्ने की पैदावार हो, चाहे चावल की पैदावार हो, जो भी किसान पैदा करता है, उसके भाव छह महीने पहले तय हो जाने चाहिए ताकि किसान उस हिसाब से बोएगा। दुर्भाग्य यह है कि गन्ने का भाव एक साल अच्छा मिला, तो किसान दो-तीन साल गन्ना बो देगा, गेहूं का ज्यादा दाम मिला, तो गेहूं बो देगा और

यदि आलू का भाव अच्छा मिला तो आलू बो देगा । इस ज्यादा बोने का असर उलट करके किसान पर पड़ता है और उसके दाम कम हो जाते हैं । लिहाजा, दामों को संतुलित करने के लिए, देश का उत्पादन न घटे, पैदावार बढ़ती जाए, संतुलित रहे, तो पहले से किसान की फसल के दाम निश्चित किये जाया करें तो यह अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA
(Gujarat): Sir, before I come to the shortcomings on the agricultural front, I would like to point out the recent declaration by the All India Congress Committee that met yesterday and passed an economic resolution. I quote:

"Among the policy areas requiring immediate attention is the question of raising agricultural productivity, particularly in areas of the country where new technologies of production have not yet made a significant impact. The AICC (I) believes that this is crucial to the removal of poverty and also to the next phase of industrialisation and the consequent expansion of associated employment. The AICC (I) urges the Government to give high priority to improving rice productivity, particularly in the eastern region. This programme, run on a pilot basis in 1984-85, holds the promise of transforming the social conditions of some of the poorest areas of our country. Several bold and innovative steps are, however, needed for its successful implementation including land reforms. The AICC (I) hopes that these aspects will receive the most urgent attention. An important element of our agricultural policy is to provide incentive to the farmers by ensur-

ing reasonable; prices for their products and supplying subsidised inputs. This strategy has paid rich dividend in the past. The AICC (I), while commending the continuation of the same strategy, welcomes the Government's decision to reorient the Agricultural Prices Commission as Agricultural Costs and Prices Commission which would vastly benefit the farming community."

So, in this paragraph an orientation has been given and the achievements of the past also have been mentioned. In the post-Independence period, the foodgrains production has almost trebled; from 50 million tonnes it has gone up to 150 million tonnes. More than 20 million tenants have been made owners of the land and irrigation potential has been tapped—something more is required to be done. But we know that this is not sufficient, because by the end of the century we would be required to produce 240 million tonnes of foodgrains and we will have to work out a new strategy. Some friends, from the Opposition have referred about agricultural production in China and Russia. They have mentioned the foodgrains production in China is 400 million tonnes and that of Russia is 180 million tonnes. The population of Russia is 25 crores, while our population is 70 crores. The availability of foodgrains per capita in our country is 430 grammes. We can understand that in socialist countries it is much more-. Here the critical point comes. Sometimes the difference is very big.

It is my understanding that apart from the question of social structure which is very fundamental, the role which voluntary organisations and political parties which ought to play

[Shri Chimanbhai Mehta!]

is not given due to the extent it is required. Even during the Janata regime this was the case. At times mainly local bodies were made to implement the policies in the agricultural sector. Unless political parties and voluntary organisations are mobilised, we cannot improve agricultural production, irrigation potential or dairy or any other thing, because this requires a massive peoples' movement, enthusiasm and new research work. All these things cannot come if we simply handover all the agricultural schemes to the bureaucracy.

Sir, the AICC Resolution rightly mentioned the incentives policy and , beneficial price policy for the farmers. Recently we have made a very important announcement that the Agricultural Prices Commission will be known as the Agricultural Costs and Prices Commission. The Government should give the farmers sufficient remunerative prices for their produce.

During 1977-78, the groundnut price had suffered. During this period in my own State the groundnut was sold at Rs. 25 to 40 per 20 kgs. That was the maximum price paid to the farmers. Later on, it came down to Rs. 25/- . But, today the price of 20 kgs. groundnut is Rs. 100/- and production of groundnut has increased. We are still importing the edible oil. But, we have to lay more stress on research programmes in the oilseeds sector, because the production of groundnut per hectare in other countries is much more than our country.

Now, one more point is required to be stressed. That is about our credit structure. As far as agricultural sector is concerned, the credit

structure is very defective. Although 42 per cent of our national income comes from the agricultural sector, we hardly provide 10 per cent of the national credit to this sector.

[The Vice-Chairman (Shri R. Ramakrishnan) in the Chair]

And also that credit becomes costly for the farmers. Sir, I would like to draw your attention to the fact that the Reserve Bank gives money to the NABARD at 4 per cent interest. The NABARD gives money to the apex bank adding 4 per cent interest. Then 2 per cent is added by the apex bank when they lend money to the district co-operative banks. Then again 2 per cent is added by the district co-operative banks when they lend money to the primary cooperatives. And the primary cooperatives add 1 per cent when they give money to farmers. Thus when the money originates, it carries an interest of 4 per cent. But when it goes to the farmers, it carries an interest of 13 per cent. The farmer who is already weak and the agricultural sector, which is suffering from several handicaps, should not be burdened with an interest of 13 per cent. This requires drastic reform. If possible, it should be very cheap credit, with an interest of 5 per cent or 7 per cent we should work it out on these lines.

I welcome the Crop Insurance Scheme because I think it will give an incentive to the farmers. We have to see how it is implemented because that is the crux of the question.

Our water resources are expanding, but hardly 50 per cent of our irrigation potential is exploited. I know about the Namada project, which is one of the very big national projects. There were regional

claims and counter-claims and, after so many hurdles, when the project was cleared, now some of the State Governments which are supposed to contribute some money to the Gujarat Government, because it is the agency that is handling the project, are not forthcoming to give the money and, therefore, the project also suffers. I would request the Government of India to take up this matter with the State Governments concerned and also try to see that this project is carried out expeditiously in a phased and time-bound manner.

Regarding fertilizer also, we require more production because there is a shortage of fertilizer and sometimes black market is also coming into this sphere. That is what we are finding.

Regarding electricity, out of more than five lakh villages, only 2.4 lakh villages have been electrified. And to exploit the water resources, we have to give electricity also a priority.

Now, Sir, 30 per cent, or a little less than that, of our land comes in the irrigated area. The rest, that is 70 per cent or more, is in the dry area zone. So unless some basic research is done on dry areas, production will not increase to the extent we desire, because it will take some time to tap the irrigation potential. It is also a costly affair. But there are several countries in the world, including Israel which does not have plenty of water resources, which are managing dry farming. Unless dry farming is taken care of, most of our poor peasants who are in dry area, will not get the benefit. So special attention should be given to dry farming,

Lastly, in the coastal areas of our country, particularly in Gujarat, I find, water is rushing into the coastal areas and the cultivated areas on the coastal side are now going out of the Agricultural zone because the land has become very salty. And the State Government's resources alone would not be able to fight against this natural problem. So, the Central Government should come to the aid of the coastal line wherever the land is found converted into salty land. Some measures should be evolved to deal with the problem.

As regards knowledge of agricultural science, I think it is high time they gave priority to University education in agriculture. They have been giving priority to medical and engineering education but Universities in agricultural education are not coming up to the desired extent. I suggest that every district must have an agricultural college and Agricultural Universities should also be established in good number. Just now Shri Sultan Singh was referring to the shortage of veterinary doctors. Some other Members were referring to lack of knowledge, that a university is a very vast complex. No, it is not like that. In a University there are many faculties. ^ In our State there are two Agricultural Universities and a third is likely to come. More Universities should, therefore, be planned and they should be established as rapidly as possible. Thank you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Chairman, the potential of agricultural economy in our country can be gauged by the single fact that if we achieve just 10 per cent increase in production

[Shri Ghulam Rasool Matto]

over the previous year's, we will be able to produce 15 million tonnes more and assuming that 5 million tonnes will be needed by us, we will be in a position to export 10 million tonnes, of foodgrains. What is 10 million tonnes worth? Even at the international price of only Rs. 2 a kilo, we will be able to earn a foreign exchange of about Rs. 2000 crores. This Rs. 2000 crores constitutes about 4 to 5 major or industrial products that we export at present. I am looking at it from this angle alone that even by achieving 10 per cent increase, we will give to the State Exchequer foreign exchange worth Rs. 2000 crores. This is not impossible to achieve if we go by the figures quoted by you yourself. In 1982-83 we achieved a production of 133.30 million tonnes and in 1983-84 we reached 151.54 million tonnes. That means an increase of 18.24 million tonnes. If we could achieve in one single year an increase of 18 million tonnes why is it not possible for us to increase the production by 10 per cent more so that we are able to export about 10 million tonnes of foodgrains and earn foreign exchange worth Rs. 2000 crores? There are other ways how this can be achieved. To my mind our production can increase, according to the world standards, to 300 million tonnes. Of course, it will take time because on the irrigation side potential has to be provided to those areas first before that target can be thought of. But a minimum target is possible under the present circumstances also. According to the Economic Survey production of rice has increased at a slow pace. I would like to quote from the very Economic Survey:

"Production of rice has increased at a slower pace than that of wheat largely because of the slow growth of production in the Eastern and Southern Regions. An analysis of the regional variation in growth rates in area, production and yields of rice shows that the northern region displayed the highest growth rates in area production as well as per-hectare yield during 1970-71 to 1981-82."

So, these are all small imbalances and if we attend more properly to the Eastern Region in the case of production, we will be able to achieve the target within the minimum possible time.

Again, I would like to quote from the Economic Survey:

"The important factors responsible for low rice yields in the Eastern Region are low coverage of area under high-yielding varieties, poor consumption of fertilizers, late sowing/transplanting and prevalence of the practice of direct seeding over large areas."

If this one aspect is attended to by the Ministry of Agriculture, our production will get revolutionised. But we do not give that type of emphasis on those areas which are identified to be our weak points. If we can attend to these weak points, then there will be improvement.

Now, let us take the case of wheat in which we are known to have achieved what is called the Green Revolution. Again, Sir, I would like to quote from the Economic Survey:

"The yield rates of wheat outside Punjab, Haryana and U.P.,

are low. While the average yield per hectare in 1983-84 in Punjab was 30.2 quintals per hectare, it was only 13.8 quintals per hectare outside Punjab, Haryana and U.P. The difference in the yield rates between the northern States and the other wheat-producing areas represents the immediately realizable potential."

Mark the words' "immediately realizable potential.". It means that it is not impossible. So, it goes on to say:

"Many progressive farmers in these areas have obtained yields as high as in Punjab or even higher. Effective extension efforts and adequate input supplies can ensure that such yield rates are the rule rather than the exception. The main constraints in wheat production in these areas are inadequate replacement of the old high-yielding varieties, low coverage areas under irrigation and low fertilizer application."

Therefore, my request to the honourable Minister would be that now that we have identified the weak points so far as these items are concerned, we should give more emphasis to this region and then alone we can achieve the target. Now, Sir, the time at my disposal is very short and I would only refer to one or two points more.

Now, with regard to pulses, our production has been very low. Again, I would like to quote from the Economic Survey:

"Production of pulses has been stagnating in India around

10—12 million tonnes for that last 20 years with the exception of 1975-76 when it reached 13.04 million tonnes. Like oilseeds, pulses are grown mainly on rain-fed lands as only 9 per cent. Of the cultivated area under pulses has irrigation facilities, Pulses are selected for their adaptation to moisture stress conditions rather than for high yields. Generally, comparatively poor quality lands are devoted to pulses cultivation. Traditional pulse-growing areas switch to other crops as irrigation becomes available. There has, however, been no overall reduction in the area under pulses as newly reclaimed and traditionally fallow areas with low-quality soil and/or inadequate irrigation facilities are brought under pulses."

Sir, in a country like ours, protein is a very important ingredient of our food. Now, even for the non-vegetarian people it is not possible to buy meat. The meat price in Delhi is Rs. 24 per kg. I can tell you that many families in Delhi itself have switched over to pulses because they have to find some alternative for proteins. And their production is stagnating for the last 20 years at 10 or 12 million tonnes. We have to do something about it. For this purpose I understand that there is need for high-yielding varieties in pulses. I am afraid this contention cannot stand the test of time. (*Time bell rings*). My point is that high yielding varieties in pulses be made available to the farmers so that the pulses production, which has stagnated for the last 20 years, is increased. This is very important. So I would request the hon. Minister to look into it and see that this thing is done.

LShn Ghulam Rasool Matto]

Now, I have two points with regard to NRDP—National Rural Development Programme. For this certain amounts have been earmarked to the States. In the State of Jammu and Kashmir same amount has been placed at the disposal of blocks—Rs. 5 lakhs—and this is being spent without calling for tenders. I would request the hon. Minister to look into this and monitor it, since this is being spent by the Centre, and so see that this amount is spent in a proper and regular way. This is being done in Jammu and Kashmir, and I would request him kindly to look into this complaint because there is a wide-spread complaint that in any block no work is done, no tenders are invited, and the amount is being spent in an irregular way. Each block spends Rs. 5 lakhs. This needs to be looked into, and I would request him to kindly look into it. *(Time bell rings)*.

You are ringing the bell and I have some points to make from the Economic Survey. But I would try to finish. I would only request the hon. Minister to take note of one thing with regard to Jammu and Kashmir, and that is that in Jammu and Kashmir we have achieved a target production of fruits worth Rs. 100 crores during the last year. Our estimate is that by the year 1990 the production will be Rs. 200 crores. Now, Sir, the vagaries of weather are more in the case of fruit-growing orchards rather than crops. I would request him that he must extend the crop insurance scheme to orchards also, because the vagaries of weather on orchards are very large. So I would request him kindly to look into this matter and see that the crop insurance scheme is extended to the

horticultural sector, both in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. This is a very important factor.

Lastly, Sir, I would like to tell him that the allocation for the agricultural production is stagnant at 16 per cent. From the same Survey Report I find that the agricultural allocation for the Plan outlay was 16.7 per cent of the entire revenues, during 1966—69, and for the current year also it has gone down to 12.3 per cent and for the annual plan 1979-80 it was 16.4 per cent only. I think that the Agriculture Ministry is not properly putting up its case to the Planning Commission to have more allocation for agriculture, and that is why it has remained stagnant. And when this stagnation is there, how are you going to achieve the goals that I have just mentioned and to achieve more growth, more production, in the Eastern States, both in rice and wheat, and also for other schemes. *(Time bell rings)* I will request the hon. Minister to look into this aspect, the financial allocations for the Plans, so that the goals that we have in mind are achieved.

Thank you very much.

6-00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): All the parties have exhausted their time. Since it is an important subject, I am giving 5 minutes to each! Member.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR! (Karnataka): Sir* I think I am unfortunate that I am getting only 5 minutes even though my chance should have been earlier. But the other speakers have taken the time. Of the total national income, 50 per

cent is provided by agriculture. I am not going into other aspects of the Ministry of Agriculture such as supply of seeds and other things. I am restricting myself only to one input which is very important for agricultural production and that is credit. The credit plays a very important part. The credit is provided by the three main institutions, i.e., the commercial banks, co-operative institutions and the regional rural banks. In 1983 the Reserve Bank of India directed all the financial institutions that they should provide 50 per cent of their total credit to the priority sector that consists of agriculture and weaker sections, before the end of March 1985 and 60 per cent of their total credit to the priority sector consisting of agriculture and weaker sections before the end of March 1987. Out of the total of 40 per cent which was fixed by the Reserve Bank for the priority sector which includes agriculture and weaker sections, the Reserve Bank has provided that 25 per cent advances should go to the weaker sections or 10 per cent of the total credit from the commercial banks should go to the weaker sections before the end of March 1985. There are nearly 138,000 base level units, 94,000 primary agricultural credit societies and 1833 branches of the P.L.D.B. and the branches of the State-owned banks. There are 42,000 branches of the commercial and nationalised banks. There are 340 D.C. banks in the country which are also providing credit. Here, Sir, if you see the total picture of this country, as one of my friends was referring to the credit in Eastern India which comprises West Bengal, Assam and other small States, is very low compared to the other States. A higher credit is provided by the Western

India, Southern India and to some extent Northern India. The credit there is much more than in the Eastern States. Therefore, we have to do something for the development of agriculture by providing adequate finances. We don't hope to achieve any substantial progress in this part of the country without adequate finance. I want to bring to the notice of the House and the hon. Minister that the deposit of commercial banks is 54039 crores as in June 1983. The agricultural advances which have been provided by the Commercial Banks amount to 5375 crores. It amounts to 10 per cent of their deposits. At the same time, 2/3 deposit of the cooperative banks has gone to the agricultural sector. What I am trying to say is that the commercial and nationalised banks should increase their lending to the agriculturists through, primary societies or direct lending. Unless they do it, we cannot fill up the gap which is already there. That gap will have to be filled up by the cooperatives and the commercial banks. Sir, the National Bank for Agricultural and Rural Development was opened with great expectation that it will provide finances for the agricultural development and also for the rural development. How far it is achieving its object? My submission is that in the initial stages, there was no Board at all. Only the Chairman and the Managing-Director were financing, and they were doing the business. I want to bring one thing to the notice of this hon. House and the hon. Minister of Agriculture. The sole purpose of the NABARD is to provide the finances. And you will be surprised to know what they are doing. They are earning Rs. 100 crores every year because their commission is 1.75 per cent. That is the margin

[Shri Veershetty Moglappa Kushnoor]

which they get. And they are getting Rs. 100 crores to Rs. 200 crores every year. Instead of utilising the money for the development of agriculture and the weaker sections in the rural areas, they have provided Rs. 200 crores for the construction of houses of their own employees and officers. And this will be very interesting to note that in some places like Bombay and Poona, they have purchased nearly Rs. 55 lakhs worth of sites for the houses of their officers and employees. And it is very interesting to note what is being discussed in the Board of the NABARD. They have got only three items in their agenda. The first item is about the employees; the second item is about the construction of houses; and the third item is about the development of agriculture. This is not the way of providing finances to the agriculture and rural development. They are thinking only in terms of their own benefit. That is not for the benefit of the rural masses or for the benefit of agricultural development. Sir, in the earlier times, there were agricultural credit boards and at the same time the Agricultural Refinance Development Corporation. They were rendering better service to the rural people and to the agriculturists. But we must go into the affairs of the new agency which has come into existence. We must enquire as to how they are doing their business and what type of service they are rendering to the agriculturists. Not only that, Sir. They are creating all sorts of hurdles in giving finances to the weaker sections and to the agriculturists. It will be interesting to note in this connection. Sir, that the commercial banks have been allowed even

¹ if their recovery is less than 60 per cent of the IRDP loan whereas in the case, of the co-operative banks, they have taken the district as a unit and if any district bank has recovered less than 60 per cent of the IRDP loan, they have denied them all the credits. In the case of the commercial banks, they have fixed the criteria of what you call the branches whereas here they have taken the district as a unit. Here, my submission is that the same yardstick as has been applied in the case of the commercial banks should be applied in the case of the branches of the District Co-operative Credit Banks. What happens is this: I will give you one example of the Karnataka State. There are 96 branches of the DCCBs. Out of them, 14 have been denied the IRDP loan. And the Ministry of Agriculture says on the other hand that the DCCBs are not at all advancing the IRDP loans; this is the hurdle; and they should achieve their objectives. *(Time bell rings)* Sir, there are a number of points which I wanted to cover. I will confine myself to the co-operatives, Sir, another difficulty which is coming in the way of advancing of loans to the co-operatives is that the NABARD is not giving credit to the full extent. In the initial stages, whatever limits are sanctioned; if they are not sanctioned continuously and there is a lot of delay. What is happening thereby is that the DCC banks also in turn do not advance loans to the agriculturists. And while examining the credit limits, even in the case of the term banks which are having their own deposits, the credit limits are reduced whereas in the case of other banks, the credit limits are higher. This is also coming in the way of advancing loans to the agriculturists.

Sir, the last point I wanted to make does not pertain to co-operatives. It is about agriculture. Here the major irrigation schemes and medium irrigation schemes are fully financed by the Government and after completion of the projects the water is provided to the ryot. They charge the water rate but they do not charge any other money. But when the farmer, the poor farmer, who digs the well, he gets the loan, he has to pay interest. In order to avoid this one, my submission to the Minister is that there should be a Minor Irrigation Corporation which we should finance and they should take only the water rate and not any interest. As in the case of wells, the farmers will have to get the loan. But here there should be no need for getting the loan. They should be charged only the water rate (*Time bell rings*). Sir, I want to say one thing. Here is a very peculiar situation. The co-operatives, i.e., the credit co-operatives are with the Agriculture Ministry, whereas the consumer co-operatives, and, what you call, the marketing co-operatives, they are with the Department of Civil Supplies. and this way there are two departments and two Ministers for this entire co-operative credit system, co-operative movement itself. Then, there is another peculiar situation. When any licence is to be issued for the co-operative sugar factory that has to go to the Civil Supplies Department. I think this comes under agro-based industries and issuing any licence should come only through the Agriculture Ministry and they should issue the licence. The Civil Supplies department does not know what is happening. In several cases they are not issuing licence to the co-operative and there are a large number of applications pending. There-

fore, my submission is that the questions of co-operative factories should come only under the Agriculture Ministry. Thanking you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): ' You have taken 12 minutes and not five.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on this subject. The importance of agriculture and agricultural productivity is very vital for the economic growth of the country because the techno-economic factor of agriculture if you analyse is nearly 44 per cent of the gross national product of the country, which comes from agriculture. Twenty-one per cent of the industrial raw material comes from agriculture and export component is also very high), if we see agriculture and other things. Besides, it gives employment to 72 per cent of the working population of the country. So, as a whole, in the ultimate economic analysis, agriculture is the backbone of economic development of this country which no Government, no planning, can afford to ignore. Unfortunately, in the history of the agricultural development for the first time from the beginning, from 1900 to 1947, almost half a century, the growth was very stagnant and the growth almost 12.5 per cent in the course of 50 years. Now, since the First Five Year Plan, a lot of emphasis was laid and during 1967-68 we saw the first green revolution and in the second phase we saw the green revolution in 1983-84. In the first green revolution we intro-

[Shri Santosh Kumar Sahu]

duced the hybrid variety of wheat and other things. In the second green revolution what we achieved last year is almost an eye-opener for the whole country, namely that we have had a record production of 151 million tonnes. It was a very healthy record. But nothing can make us complacent because ultimately if we want industrial growth, if we want the growth of this country, 60 to 70 per cent of the people depend upon agriculture, it is essential that we have to take a very pragmatic, dynamic research technology oriented to agriculture view in the coming future. That is what the Prime Minister has very rightly told some two days back that we have to introduce the high-technology in the field of agriculture because until we try to improve upon the productivity of agriculture it is very difficult that India can go ahead with progress in the coming years. First thing we see here is that population is much more and the land mass is limited. So, the incidence of population on land and the ratio is unfavourably placed in the developing countries of the world and we have to feed 70 crores of people, 700 millions of people, which will become 1000 millions within some decades. The first and fundamental problem is to increase productivity. Many of my friends have already pointed out. We know that 90 per cent of the procurement of food is from out of 3 or 4 States only. So, we can say that technological growth and the impact of green revolution has not been there in other States and other States have remained neglected. There is thus a very wide gap which must be covered. I would say especially about the eastern region comprising Orissa, Bihar, Assam and other places where pro-

ductivity has not grown. I would stress upon the hon. Minister that special emphasis must be made in the less-growing areas for use of new technology for the benefit of the farmers and efforts must be ; geared up in that direction without which probably we will find some political problem or the other coming up. So, this is a fundamental problem which has to be tackled.

Sir, with regard to production of wheat, we have seen that a miracle has been achieved because of the efforts of ICAR and other such institutions. From a production of 10 million tonnes of wheat in 1967, we have gone to 42 million tonnes of production in 1983-84 but in the case of rice, we have been able to increase production only from 40 to 52 million tonnes. In Southern parts of India and in Eastern India, rice is more in demand but we have ; not been able to achieve a higher rate of production when we compare our country with other countries of the world like Malaysia and other countries and we find our productivity too low. It is the need of the hour that emphasis must be paid on increasing production of rice¹ upon which many people depend.

We have seen that for agricultural development and for rural development Government is having massive anti-poverty programme? like the IRDP. We must also reorient our approach to the problem. Since time at my disposal is short, I would only like to touch a few points. Sir, I, R.D.P. is mainly concerned with identifying poor people and providing employment for them. If we have an integrated planning, not only the people would benefit but the area would also generate more

production for the country. Then, Sir, the benefit of these programmes has not percolated to the poorer sections and there is a wide gap which has to be covered. NABARD which made a study of it has pointed out that only 18.7 per cent of the benefit has gone to rural people for their upliftment above the poverty line. I would strongly urge that self-employment is a very important factor in the economic development of the country and it cannot be neglected. What is needed today is integrated and coordinated approach so that benefit of these programmes go towards betterment and economic development and growth of the country. We can also study the agricultural development from the consumption of fertilisers. Uptil now, per hectare consumption of fertiliser in the country is only 40 Kg per hectare whereas in China where they depend on organic manure, it is 150 Kg as per 1981 study. So, there is a lot of potential which can be developed.

Another important thing is, we have to see how we can develop our horticulture and fruit cultivation. I may here remind the House about the development in Himachal Pradesh. Probably, 50 years back, Himachal was a poor State where there were no orchards. Thanks to the missionary spirit of a prominent couple who brought an apple tree from America. They experimented it in the field there in Himachal and developed it and we can see the growth and development of orchards in Himachal Pradesh.

What we find is that in research institutes, ICAR and other institutes, there is a communication gap. So, our expansion and research work must be oriented and we should have the missionary spirit to

develop varieties. *{Time bell lings}*. Because the time is short, and you have already rung the bell, I would only like to concentrate on a few points with regard to development of agriculture in my State. Sir, two sugar mills are already working. In regard to another two, licence has been given. But the people have been demanding from 1968 that there should be a sugarcane research institute or a breeding centre. But such research institutes have not been established in Orissa. I suggest that atleast in Aska and other places, such institutes should be opened.

Sir, I would say that in regard to commercial crops, the eastern States are lagging behind. More importance should be given to commercial crops like coffee, tea, in these States and the ICAR, IARI and other institutions can help in this direction. They should see that some institutions are developed in the Eastern Region, specially, in Orissa, so that the money meant for agriculture and the schemes are properly monitored, evaluated and the benefits of research flow to the people. This is the only way in which we can develop.

Sir, we should see that agriculture is given the top-most priority because it is the pillar of success. This is especially so in a country like India, where 72 per cent of the population get employment from agriculture and we have to feed the growing population which will increase to one hundred crores¹ in some decades. Therefore, unless we give high priority to agriculture and allocate more money in the Budget, we will not be able to develop. I would suggest to the hon. Minister through you, Sir, that it requires not only integrated planning.

[Shri Santosh Kumar Sahu] but other technological methods should also be adopted like soil testing and so on. Such an integrated planning should be undertaken not only in selected places, but in every district. This is essential because we want to adopt a scientific basis of cultivation, without which we will not be able to achieve the goal. We know that in the developed countries, the incidence of people on land is much less. But in India, we cannot ignore the fact. We should see that every inch of land is properly utilised and the benefits of high-yielding varieties and other modern technological methods reach the farmers automatically.

Then, the crop insurance scheme announced by the Government Has raised certain hopes. I would suggest that we should be careful in this regard and see that the benefits go to the really affected people. The programme should be pragmatic so that the people will be really benefited and the people will get what they expect from the crop insurance scheme. In the Eastern Zone, from West Bengal, including Tamil Nadu, the cyclones and other natural calamities are a normal occurrence. They destroy the backbone of the farmer. When the farmer goes for new technology or high-yielding farming, he has to invest more and once his crop is destroyed, his backbone is destroyed. He cannot rebuild himself so that he can reap the benefits of green revolution. But with the crop insurance scheme, if we are able to cover these people and also take some permanent measures for solving the problems arising out of natural calamities, probably, the farmer will get a boost and every area will be able to produce much

more foodgrains which will be required in the future.

In the end, I would say that we have done a lot for agriculture. Institutions like the ICAR, IARI and others have contributed a lot. But we should go still further and we should go at a rapid pace. We should see what problems we are facing in a competitive world. The whole economy is interconnected with the development of agriculture. Planning Commission should give special emphasis to this. Ultimately, planning should begin from the grass-roots level, that is, through agriculture, animal husbandry and horticulture. These are the three basic things only through which we can improve the common man's economic life. Planning Commission should reorient its attitude in this direction and its staff should also be attuned to this task. Only then, the benefits of the anti-poverty programmes will go to the people in every area, and not only the individual's economic condition will be improved, but the whole area as such will be improved. Only then, we will be able to achieve the goal.

Lastly, I would say that the Government should see that the benefits of research reach out to the people in the field. The condition of the agriculturists should be improved. The most important thing is that the benefits should be maintained. Otherwise, whatever we may achieve will not have any meaning. This is the weakest point. That is why, the common man is not very much interested in any organisation, whether it is financial organisation or co-operative organisation. The bureaucratisation and red-tape should be eliminated. Then only, people will be enthused

to take advantage of these programmes. Sir, the Prime Minister has rightly said that technological revolution should be applied to agriculture.

So, Sir, I can say that we are proceeding in the right direction and India can achieve the required target in agricultural development.

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन्) :
खाली पांच मिनट ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरि-
याणा) : ये पांच मिनट की जगह 15
मिनट बोले हैं। मैं बोलूंगा भी नहीं।
टेलिविजन वालों और ए० आई० आर०
वालों से कह दें मेरा नाम दे दें और मेरा
फोटो भी लगा दें।

महोदय, पहले तो मैं आप का
शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मुझे
तो शक हो रहा था कि शायद मुझे
शहरी विकास के ऊपर बोलना पड़ेगा
क्योंकि मैं खेती तो अपने हाथ से करता
हूँ, शहर की बात जानता तो हूँ नहीं।
आपका धन्यवाद कि आपने टाइम
तो दिया।

महोदय, मैं इन दोनों हाउसेज में
17 साल से चक्कर लगा रहा हूँ।
हर बार यही सुनता हूँ, हर एक मेम्बर
लोक सभा में बोलता रहा, जो भी
एग्रीकल्चर के ऊपर बोलता है वह यही
कहता है कि 'एग्रीकल्चर इज द बैकबोन
आफ दि इकानामी' (कृषि इकानामी की
रोड़ की हड्डी है) और मैं कहता हूँ कि
यह टूटने को हो रही है। जो खेती
करने वाले एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वे
भी देख लिये, जो वगैर खेती करने वाले
हैं वे भी देख लिये। आप बोल रहे थे,
आप ने किसानों के मसीहा चौधरी
चरण सिंह का नाम भी ले लिया।
मैंने वह समय भी देखा जब चौधरी
चरण सिंह मिनिस्टर थे। मैं आप
से अर्ज करूँ कि एग्रीकल्चरिस्ट्स को

288 RS—11

स्लोगन्स के ऊपर फीड किया जाता है।
महात्मा गांधी '48 में कह कर गये थे कि
जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा, गांव की
तरक्की नहीं की जायेगी, उस वक्त तक
भारत को आजाद नहीं मान सकते। फिर
जवाहर लाल जी ने भी यह कहा, फिर देश
की प्रधान मंत्री, जो बड़ी महबूब थी,
इन्दिरा जी वह भी यही कहती रहीं कि
जब तक ग्रामीण विकास न होगा तब तक
देश के अन्दर तरक्की नहीं हो सकती।
अब हमारे यंग डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर
भी यही कहते हैं। 35 साल से
यह बात कही जा रही है। कब होगा
ग्रामीण विकास? चौधरी चरण सिंह जी
ने देश की इकानामी पर एक किताब
लिखी। हमने सब देख लिये। किसानों
के मसीहा भी देख लिये इस कुर्सी पर
बैठे हुये। बीरेन्द्र वर्मा जी चले गये।
चौधरी चरण सिंह पहले तो होम मिनिस्टर
बने।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO
JADHAV (Maharashtra) : Not a single
opposition Member is there. When such an
important discussion is going on, they
should take it with some more seriousness.
Nobody is there even to listen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R.
RAMAKRISHNAN): I am
having a double role.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO
JADHAV: This is how they are serious
about our country's agricultural
development.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R.
RAMAKRISHNAN): I will convey your
feelings to them.

श्री सत्यपाल मलिक : राजीव जी
की मीटिंग में चले गये हों तो बात
दूसरी है, नहीं तो उनको बताना चाहिये
था।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मेरे
पांच मिनट हैं, मेरा भाषण हो जाने
दो। मेरे कहने से तो सारी पोलिसी

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

वहाँ बदल जायेगी। मैंने तो पहले ही बता दिया कि मुझ बोलने का बहुत शौक नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि एग्रीकल्चर के लिये समय नहीं है जबकि दो दिन तक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री पर, टेलीफोनो पर बहस-मुबाहिसा होता रहा था। और जिस को कंट्री की बैकबोन कहा जाता है, कृषि को, उस की बहस पर चाबुक लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खत्म करो। इस से ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हम कितने सीरियस हैं अपने देश की कृषि की पालिसी को आगे बढ़ाने के लिये। मैंने तो आप से अर्ज किया कि मैं एक, दो प्वाइन्ट ही आप से अर्ज करना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह के जमाने में ही शूगर केन को खेतों में जलाया गया था। यह उन की गलत पालिसी की वजह से हुआ था। आलू की हालत क्या थी उस जमाने में जब कि वह फाइनंस मिनिस्टर थे। एक किसान का आलू का ढेर पड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। इसको मंडी में क्यों नहीं ले जा रहे हो तो उसने कहा कि मंडी में ले जाने से तो वहाँ ले जाने तक का किराया भी नहीं मिलेगा। तो मैं ने पूछा कि फिर इस के पास क्यों बैठे हो तो उसने जवाब दिया कि मैं इस लिये बैठा हूँ कि कहीं कोई दूसरा अपना आलू मेरे ढेर के साथ न मिला दे। वैसे तो मैंने कभी ट्रांजिस्टर खरीदा नहीं लेकिन एक दिन सत्यपाल मलिक साहब के पास बैठा था तो उस में सुना कि :

‘रामचन्द्र कह गये सिया से, ऐसा कलियुग आयेगा,
जगजीवन राम बनेगा डिफेंस मिनिस्टर,
जाट बजट बनायेगा।’

यहाँ जब चौधरी साहब वित्त मंत्री थे तो लोग ऐसा ही गाना गाने लगे थे। मैं अपने मिनिस्टर साहब से कहता चाहता हूँ कि रोटी के टुकड़े फेंकने की जो पालिसी कृषि के लिये चलायी जा रही है उसको खत्म कर के इस को रिव्रोरेयेंट करिये। आप ने किसानों को क्या दिया? हरियाणा में बिजली नहीं, पानी नहीं। पानी पाकिस्तान को जा सकता है लेकिन हरियाणा की नहरों

को पानी नहीं दिया जा सकता। आप वहाँ के किसानों को पानी दें, बिजली दें, खाद दें और किसान को उसके रहम पर छोड़ दें; वह आप की कृषि की पालिसी को चलाता रहेगा। आप उसको यह चीजें मुहैया कर दें। मैं इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता। इस पर केवल एक ही बात कहना

most fertile Land are
being: acquired for mc'u;-tri; 1 pun

एक किसान मुझ से पूछने लगा कि हम खेती कहाँ करेंगे। हमारी सारी उपजाऊ जमीन तो इंडस्ट्री के लिये ले ली जाती है इसलिये मुझे याद आता है कि बर्ड्सवर्थ की एक पोयेट्री The Decent Villages है जिस में उसने कहा है :

"Princes may come, or may fade;

A breath can make them, as a breath has made;

But a bold peasantry, a country's pride,

When once destroyed, can never be supplied."

अगर किसानों के साथ और उस की जमीनों के साथ इसी तरह का खिलवाड़ होता रहा तो मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप की कृषि कमीशन नहीं पायेगी। यह ठीक है कि भारतवर्ष का किसान बहुत मेहनती है। मैं समझता हूँ कि हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं और उन्होंने किसानों को काम करते देखा है। अगर हमारे मेम्बर साहब एक दिन भी खलिहान में श्रमिग जो होती है उस समय वहाँ रहें या जब गेहूँ की कटाई होती है उस समय वहाँ चले जायें तो शायद अगले दिन यह हाउस लगेगा नहीं। गेहूँ का रंग लाल ऐसे ही नहीं होता है। गेहूँ पैदा करने में किसानों का खून गेहूँ में चला जाता है तब जाकर गेहूँ का रंग लाल होता है। इन सारी चीजों को देखते हुये मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातें नहीं बोलना चाहता लेकिन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ

क्योंकि उन्होंने पालिसी बना दी कि आप इन्फ्लेक्शन होगो। इसके लिये स्कीम भी आयेगी, सरकार उसका प्रचार भी करेगी; लेकिन किसान बेचारा समझता नहीं है। पता नहीं यह स्कीम कब तक उनके पास पहुँचेगी और कितने वक्त के अन्दर इसको लागू किया जाएगा। जैसे और चीजों में किसान को देना पड़ता है, 50 परसेंट ही चीजें उसको मिल पाता है, बाकी 50 परसेंट उसका रिजर्व के अन्दर चला जाता है, इसके अन्दर भी पता नहीं क्या होने वाला है। बहरहाल, गवर्नमेंट का शिफ्ट तो बहुत कर रही है। अगर इनके अन्दर अगर किसान की मुश्किलों को आप कम कर सकें, उसकी मुश्किलों का अहसास करते हुये उनकी प्राबल्य को अंडरस्टैंड करते हुए उनको सहायित्व दी जायेगी तो देश तरक्की कर सगता है। मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ, आज भी यही कहता हूँ कि किसान को उसके रहम पर छोड़ दो लेकिन उस को जिन चीजों की जरूरत है खेती के लिये, वे सारी चीजें उसे मुहैया कर दो।

इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खास तौर से मेरा नाम उठाकर मेरे काम के लिये किया।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: I stand corrected, Sir. It is Goldsmith.

SHRI DINKARRAO GCVIND-RAO PATIL (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, before submitting my suggestions, I must congratulate the Government of India for making India self-sufficient in food and for introducing the crop insurance scheme which will benefit the small and marginal farmers.

Rut, here I must throw light on a naked truth and a hard reality,

that there are still persons who are residing under the shelter of the sky. There are persons who cannot get food two times a day. There are persons who have not a single pie even to buy a small bottle of poison to drink and die. There are persons who do not have even three feet of land of their own to cremate their own dead bodies. This is the situation in the rural areas of our country. Therefore, Sir, in this background I want to suggest that the need of the day is to define the word "farmer". A person who cultivates a farm, who works in a farm and because of whose work and perspiration the agricultural production is growing, should be called a fanner. The land belongs to him only. The definition of "landlord" must be removed. A person who enjoys at the cost of the work and perspiration of the cultivators cannot remain the lord of the land. Land should, therefore, be distributed in such a way that neither a person should remain lord of the land nor should anybody remain a man without land. This should be the basic philosophy behind agricultural production and rural development revolution.

The next point is whether remunerative prices for agricultural products should be fixed on the basis of cost of production. My submission is that instead of doing this, the costs of means or inputs required for agricultural production should be lowered down. Because, Sir, take water, for example. No doubt, scarcity of water is a natural phenomenon, but I find that man has created artificial scarcity of water. We find that there is theft of water, there is corruption in supply of water. There is wastage of water by his landlords who deprive the right of the people to have

[Shri Dinkarrao Govindrao Patel]

drinking water. Thousands of acres of salty land does not need water. Yet water is being supplied to it. On the other hand, millions of acres of land is thirsty, but it does not get water. Therefore, my submission is that the hon. Minister should prepare a comprehensive scheme so that water for irrigation is supplied on the basis of some priority. First, water to human beings to save them from the thirsty-deaths. Second, water for the food crops to save the poor people from starvation. And last, water for cash, commercial crops like sugarcane, grapes, tobacco, belonging to the established landlords.

Electricity, fertilizers, agricultural machines like tractors, ploughs etc.—these factors should be made available at cheap prices on a priority basis to the small holders and middle farmers who are growing foodgrains. We should apply this criteria and principles in the development of the agricultural production.

There is no need for raising day in and day out the prices of the bread of the poor people. The reactionary movement of the established farmers, started by Shri Sharad Joshi in Maharashtra and that even in Punjab will come to an end.

The next point which I would like to make in short is about the use of technology and science. I am proud of the application of science and technology in agricultural development. But the agricultural workers should not become the victims of such technology and science. It is fear that science may reduce the work, and the agricultural workers will remain without

work. Thereby, the problem of unemployment will increase. So, the hon. Minister should take care of such a danger. The hon. Minister should take care also that science and technology should not become »< harmful to land and agricultural production. Excess of fertilizers makes food harmful and tasteless also.

My next short point is about the distribution of food. Though India has become self-sufficient in food, still, we find, in the backward and ^ tribal areas the poor people are not * able to get sufficient and good food. In fact, there is no scarcity of food in India. Man has created artificial scarcity in India. Therefore, I request the hon. Minister to make the distribution machinery strong and powerful to carry food to the poorest man in India.

Then, the last point which I would like to make in short is about the defects in the implementation. Why defects Sir? Who are controlling the sugar factories? The co-operative marketing federation: the co-operative banks? The answer, Sir, is, the big landlords who have got the political power, they are controlling these institutions. So, my submission, Sir, is that this economic and social structure must " be changed through agricultural development.

Then, my last point which I would like to make in short is about the unemployment problem in the ru^al areas. I may suggest that the basic philosophy should be like this. that those who have got sufficient economic resources should devote their time in the service of the nation and society without any return. They may be given the honour for their self-less services, but not money which poor people can claim as their right. Those who

are landless and are below the poverty line should be given employment in various fields.

Last, but not the least, the problems of the villages. I regret to say, Sir, that the villages are in the same conditions as they were before the Independence. There are no new roads in the villages. There is no new structure of agriculture. On the other hand, I find in the villages one or two liquor shops which spoil the character of the villager. Therefore, I suggest that the young farmers and workers should get better deal. They should be provided good dwelling places. They should be provided with good books. They should be provided the best of music, dramas and films to save these young farmers from the disastrous. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The last speaker. Mr. S. N. Deshmukh. We are having very big audience.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, much has been discussed, debated and said over the Ministry of Agriculture and lot of farmers. I will not go into the points that have been mentioned by the previous speakers. Sir, time has shown and experience has proved that green revolution has created a special peasant class which has not removed the poverty of the common farmer. All our efforts, programmes, schemes, bank loans that have been extended to them have gone astray. But the main point that was discussed here very seriously was about the price of the market produce.

I am myself being a farmer, I know what type of difficulties a farmer faces in disposing of his farm produce. In the Nasik dis-

trict of Maharashtra onions have become rotten for want of proper price. Our farmers have been hounded out by urbanised people. The farmers are facing very grave problems not in one State but throughout the country. The farmers are being hounded out by the urbanised people with regard to their market produce, their lands and their inheritance.

If a farmer's land falls within an agglomeration area which is around a certain town comprising minimum twenty-five villages, it becomes an urbanised land. Further, if the land is shown for any other purpose other than agriculture in the town planning map, the land is declared as a vacant land. And the owner is entitled to a fraction of land—2,000 sq. metres—that means—one biga or half an acre. This is the irony. He is entitled only for 2,000 sq. metres. If he has got a major son, he will get another 2,000 sq. metres. But, if he has got a minor son or daughter, he will not get anything. When a farmer's property is taken under the Urban Agglomeration, or under the Urban Land Ceiling and Regulation Act or Urban Land Ceiling and Regulation Act, he will be paid very meagre amount. Under section 14 of the Act, 25 per cent of the price will be paid in cash. And what price? Five rupees per square metre, which is 100 times below the market price. And 75 per cent will be given after 20 years. What a luck? Can the farmer go to a shop and say, "Here is Rs. 25; I will pay Rs. 75 after 20 years"? See the hounding up and rounding up of the farmer. I will read the provision. Sir, for your information.

"Twenty-five per cent of the amount or Rs. 25,000, which-

[Shri Shankarrao Narayanrao Deshmukh]

ever is less, shall be paid in cash and the balance in Negotiable Bonds redeemable after the expiry of twenty years."

What a fate? Supposing that within these 20 years the man dies, what about the succession? What about his heirs? Do they get the money? And with that 25 per cent in cash, what can he do? Suppose he gets Rs. 5,000. Can he buy a buffalo? Can he buy goats and start a butcher's shop? This is simply an irony of fate. And this is *for* what? For urbanising the land. For the benefit of the urban people, the rural people are to be rounded up and hounded up. And to whom are these lands given? Section 23 says:

"It shall be competent for the State Government to allot by order, in excess of the ceiling limit, any vacant land which is deemed to have been acquired by the State Government under this Act or is acquired by the State Government under any other law, to any person for any purpose relating to or in connection with, any industry or for providing residential accommodation of such type as the Government may deem fit."

That means, you want to deprive the farmers in all these 15 States and two Union Territories, out of their farming and give their lands to whom? To those people who will urbanise it. Sir, they have not stopped there. They say that the provisions of this Act will override any other Act. Section 42 says:

"The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith in any other law for the time

being in force or any custom, usage or agreement or decree or order of a court, tribunal or other authority- ..."

So the heirs of a farmer cannot go in for a succession certificate. The price is fixed. The farmer cannot go anywhere for, any increase. And what is the intention of the Act in removing these lands from the farmers? It was this:

"An Act to provide for the imposition of a ceiling on vacant land in urban agglomeration, for the acquisition of such land in excess of any ceiling limit, to regulate the construction of buildings on such land and for matters connected therewith, with a view to preventing the concentration of the urban land in the hands of a few persons and speculation or profiteering."

Were the farmers speculating or profiteering? They have been, from generation to generation, doing farming. Now, I am not pleading the case of absentee landlords who have got their lands in villages and who stay in Delhi, Calcutta or Bombay. I am not pleading the case of those who have divided, their lands into plots and are waiting for speculation. I am pleading the case of those farmers who cultivate their lands personally and use it for agricultural purposes only. A difficulty was experienced in old days and, therefore, article 31A of the Constitution was amended. The second proviso of article 31A says:

"Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate or wherein any land comprised therein is held by a person under personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of

such land as is within the ceiling limit applicable to it under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant there-to unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure provides for the payment of compensation at a rate which shall not be less than the market rate."

Therefore, my submission is if you want to take the land from the farmers, you pay them the market price as per the provision under Article 31A Proviso 2 which is included in the Fundamental Rights Chapter. If you do not want to give the farmers that price, then delete that definition of 'vacant land', delete Explanation C of clause (o) of Section 2 under the Acquisition Act so that the lands which are shown in the Town Planning Act 'for any purpose other than agricultural' will not be considered as vacant land. Unless you delete that provision, it shall not be lawful or it shall not be just considering the farmers' plight. Thank you very much for having given me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ft. RAMAKRISHNAN): We have had a very long and interesting discussion on this very important Ministry. This concludes the discussion here and the honourable Minister will reply tomorrow after the Calling-Attention. The House stands. ..

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: On a point of order. There are only two speakers who have been present. All other speakers have escaped. The Parliamentary Affairs Minister is there because she cannot escape. . And the Minister for Rural Development is there, you are there in the Chair, and I am the only other speaker but who is a non-speaker. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ft. RAMAKRISHNAN): We thank you very much for being present. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past six of the clock, till eleven of the clock, on Tuesday, the 7th May 1985.